आया है। क्षेत्रफल बढ़ाने के साथ–साथ और किसान इसका पूरा लाभ उठाने को तत्पर है।

कतिपय सुझाव

परम्परागत कृषि विकास योजना भी अन्य सरकारी योजनाओं की राह पर चल पड़ी है। इसमें किसानों को कागज ज्यादा और कमाई कम नजर आती है। उसे पंजीकरण के नाम पर बार–बार कतारों में खड़ा होना पड़ता है। पहले तो इस योजना के अन्तर्गत उसका नाम आने पर उसे अपना, अपने परिवार, अपने श्रोतों का विवरण देना पड़ता है। तत्पश्चात् उसे खसरा और खतौनी की प्रतिया भी बार–बार देनी पड़ती है। विपणन की सुनिश्चित व्यवस्था हो। अतिउत्तम हो यदि किसान को जैविक उपादान भी दिये जाये। पीजीएस पद्धति से प्रमाणित उत्पाद विदेश में जैविक उत्पाद के रूप में नही भेजा जा सकता। जैविक खेती के उपादान या तो किसान स्वयं बनाता है अथवा उसके लिये धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। इसमें अधिकांश किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाजार में उपलब्ध उपादानों की विश्वसनीयता संदेह पूर्ण है। अतः सरकार को गुणवत्ता पूर्ण उपादानों को क्रय करके किसानों को अपने माध्यम से उपलबध कराया जाये। अतः सरकार को इसमें परिवर्तन करके निर्यात योग्य बनाना चाहिये। उपरोक्त सुझावों को लागू होने पर किसानों के जैविक खेती करने में जो कठिनाईया आती है या खटास का अनुभव होता है वह सब मधुर अनुभव में बदल जायेगा।

निष्कर्ष

जैविक खेती एक गैर रासायनिक और परम्परागत खेती है जिसका उत्पाद प्रमाणित कराकर अच्छे दामों में बेचा जाता है। इससे सकल एवं शुद्ध लाभ किसी भी खेती से अधिक होता है।

अतः जैविक खेती से पैदावार कम या हानि होगी यह मात्र एक भ्रान्ति है। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित और उत्तर प्रदेश कृषि विभाग द्वारा संचालित इस योजना में गोरखपुर के 2500 किसानों के अनुभव बड़े ही सार्थक और अनुकरणीय रहे है। जैविक कालानमक धान की खेती से शुद्ध लाभ रूपया 92500 प्रति हैक्टेयर प्राप्त हुआ जबकि अधिक उपजशील धान की प्रजाति बीपीटी 5204 से मात्र रूपया 17500 मिला। आर्थिक लाभ के साथ–साथ जैविक खेती से खेत की मिट्टी और पानी भी शुद्ध हुआ तथा उत्पाद खाने से परिवार का स्वास्थ्य भी सुधरा। अतः गोरखपुर के किसान जैविक खेती करने के पक्षधर है। प्रमाणीकरण में गोरखपुर स्थित संस्था पीआरडीएफ का सराहनीय योगदान रहा है।

कुदरत का कहर : बेमौसम बरसात

राकेश कुमार एवं पवन जीत

"मौसम ने पिछले कुछ सालों से हमें चौंकाने का जो सिलसिला शुरू किया है वह अभी भी कायम है। अतिवृष्टि और अनावृष्टि वैसे तो जब-तब हमारे लिए मुसीबत के रूप में आती-धमकती ही रही हैं, लेकिन बारिश का बदलता चक्र अब अलग तरह की परेशानियां ला रहा है।"

मार्च के महीने में देश के इतने बड़े हिस्से में इतनी तेज और इतनी लंबी बारिश कोई सामान्य बात नहीं है। जिस पश्चिमी विक्षोभ का हवाला मौसम विभाग ने दिया है, उसकी व्यापकता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उसने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर यानी देश के पूर्वी–पश्चिमी दोनों छोरों से नमी उठाई थी। कृषि विशेषज्ञों ने रबी फसलों की पैदावार और दलहन उत्पादनों में भारी गिरावट आने और फसलों की गुणवत्ता के प्रभावित होने की आशंका जताई है। जाहिर है कि इस स्थिति के चलते महंगाई भी बढ़ेगी ही। केंद्र सरकार ने फसलों को हुए नुकसान के बारे में राज्यों से सूचनाएं मंगवाई हैं। नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

बेमौसम बरसात की मार से गेहूं, चना, मसूर, सरसों, धनिया, मटर, संतरा और आलू की फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। लेकिन जहां गेहूं में अभी बाली नहीं फूटी है, वहां नुकसान की संभावना कम है। कटाई के लिए तैयार खड़ी गेहूं और चने की फसल खेतों में ही बिछ गई। इससे दाने में दाग लगने या दाने छोटे रह जाने की आशंका बढ़ गई है। चना और मसूर के साथ धनिया और सब्जियों के लिए भी यह बारिश जानलेवा साबित हुई है।

आम के पेड़ों में लगे बौर के लिए भी यह बेमौसम की बारिश नुकसानदेह साबित होगी। खराब मौसम की वजह से गेहूं की खड़ी फसलें जमींदोज हो गई हैं। तेज हवा से उन किसानों को ज्यादा नुकसान हुआ है, जिन्होंने मौसम बिगड़ने से पहले गेहूं की सिंचाई कर दी थी।

मौसम की इस मार का असर गेहूं की फसल पर पड़ेगा। इससे दाना कमजोर तो पड़ेगा ही, उसमें दाग भी लग जाएंगे। गेहूं की खेती करने वाले किसानों पर इस मार का असर इसलिए भी ज्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि फसल के दागी होने के कारण किसान को फसल का उचित मूल्य नही मिलेगा। राज्य सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद भी लगभग बंद कर दी है। केंद्र सरकार ने भी प्रदेश के कई जिलों में मनरेगा योजना से हाथ खींच लिए हैं, जिसकी वजह से छोटे किसान और खेतीहर मजदूरों को राहत कार्यों से होने वाली थोड़ी–बहुत आमदनी

भी बंद हो गई है। ओलावृष्टि की वजह से कई पालतू पशुओं की मौत भी हुई है।

वैसे हमारे मौसम विभाग के अफसर अभी तक निष्ठापूर्वक इन संकेतों को पकड़ते रहे हैं और हमें इनके बारे में जानकारी देते रहे हैं। लेकिन यह मामला सामान्य ढंग से आसमान साफ होने, बूंदाबांदी या भारी बारिश होने या तापमान इतने से उतने डिग्री के बीच रहने के पूर्वानुमान तक सीमित नहीं है।

ज्यादातर राज्य सरकारें अपनी आर्थिक बदहाली का हवाला देते हुए किसानों की हालत पर घड़ियाली आंसू बहा रही हैं और मदद के लिए केंद्र सरकार का मुंह देख रही हैं, जबकि केंद्र सरकार मदद संबंधी नियमों का हवाला देते हुए अपना पल्ला झाड़ रही है। संसद के दोनों सदनों में विभिन्न दलों के सांसदों ने भी इस स्थिति पर चिंता जताई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि किसानों को संकट से उबारने के लिए सरकारों को हर मुमकिन कदम उठाने चाहिए, लेकिन साथ ही मौसम की लगातार बदलती चाल जो संदेश दे रही है, उसे भी हमें गंभीरता से समझना चाहिए।

निष्कर्ष– मौसम की बदलती चाल के लिए जिम्मेदार ऐसे कारक जो संदेश हमें दे रहे हैं, वह काफी गंभीर हैं। इन्हें समझने में जिस तरह की सतर्कता और तत्परता हमें दिखानी चाहिए, शायद वह हम नहीं दिखा पा रहे हैं। समूचे देश खासकर उत्तर और मध्य और पश्चिमी भारत में पिछले दिनों हुई बेमौसम भारी बरसात और ओलावृष्टि अपने साथ खेती–किसानी के लिए आफतों की सौगात लेकर आई।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना